खुदरा बिक्री केन्द्र	आरम्भ की गयी		आरम्भ नहीं की गयी	
	आर ओ	एसकेओ एलडीओ	आर ओ	एसकेओ एलडीओ
इलाहाबाद . . .	2	3	1	0
लखनऊ . . .	2	0	2	0
रायबरेली . . .	0	2	5	1
वाराणासी . . .	3	0	1	0
सुल्तानपुर . . .	1	1	5	5

जमीन के उपलब्ध नहीं होने तथा आवंटितियों द्वारा वांछित लाइसेंस प्राप्त करने में देर के कारण इन्हें आरम्भ करने में विलंब हुआ है ।

Closure of ONGC'S Operations in Nagaland

8050. SHRI BHADRESWAR GOH-AIN: Will the Minister of PETROLEUM AND NATURAL GAS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that crores of rupees have been lost by the ONGC for closure of its operations in Nagaland;

(b) what is the total amount of loss incurred by the ONGC after its closure, so far;

(c) what is the present position of negotiations between the ONGC and the Naga Students Federation; and

(d) what is the charter of demands of students and where is the point of difference between them?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (CAPTAIN SATISH SHARMA): (a) Yes, Sir.

(b) Total revenue loss incurred by ONGC so far is about Rs. 49 crores.

(c) ONGC have not held negotiations with the Naga Students Federation.

(d) Does not arise.

देश में ही उत्पादित कच्चे तेल तथा आयातित कोच तेल की लागत में समानता

8051. श्रीमती सुषमा स्वराज :
श्री राम जेठमलानी :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में उत्पादित कच्चे तेल की उत्पादन लागत का आकलन किया है ;

(ख) यदि हां, तो देश में वर्ष 1994–95 के दौरान उत्पादित कच्चे तेल की औसत उत्पादन लागत राष्ट्रीय स्तर पर क्या थी ;

(ग) क्या यह सच है कि यह दर वर्ष 1994–95 के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य की तुलना में कम थी ;

(घ) यदि नहीं, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं ;

(ङ) क्या सरकार ने देश में ही उत्पादित कच्चे तेल तथा आयातित कच्चे तेल के मूल्यों को देश में समान-स्तर पर लाने के लिये कराधान ढांचे में परिवर्तन करने का निर्णय किया है ; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश शर्मा) : (क) से (घ) सरकार ने वर्ष 1994-95 के लिए स्वदेशी क्रूड की उत्पादन लागत का अभी तक निर्धारण नहीं किया है ।

(ङ) और (च) कच्चे पेट्रोलियम तेल पर 35 प्रतिशत आधारभूत सीमा शुल्क लगता है और इस पर काउन्टरवेलिंग शुल्क नहीं लगता । इस पर उत्पाद शुल्क से पूरी तरह छूट है और तेल उद्योग विकास अधिनियम के अंतर्गत इस पर 900 रुपए/मी० टन का उपकर लगता है । वर्तमान समय में कच्चे पेट्रोलियम तेल पर सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में परिवर्तन करने के लिए कोई भी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

तेल शोधक कारखानों के बारे में गांगुली समिति की सिफारिश

8052. **श्रीमती सुषमा स्वराज :**
श्री राम जेठमलानी :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गांगुली समिति ने सरकार से सिफारिश की है कि वर्तमान में देश में कार्यरत तेल शोधक कारखानों में अपनाई जा रही तकनीक में परिवर्तन करने की आवश्यकता है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि देश में उचित तेल शोधन व्यवस्था न होने के कारण देश में उत्पादित कच्चे तेल का परिष्करण विदेशों में कराया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों अर्थात् 1992-93 से 1994-95 के दौरान देश में उत्पादित कितने कच्चे तेल का परिष्करण विदेशों में कराया गया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश शर्मा) : (क) और (ख) समिति ने अपनी अंतिम रिपोर्ट अभी प्रस्तुत नहीं की है ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

देशी और विदेशी तेल शोधक कारखानों में उत्पादन लागत

8053. **श्री राम जेठमलानी :**
श्रीमती सुषमा स्वराज :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में कार्यरत तेल शोधक कारखानों के कार्य संचालन में व्यापक सुधार करने की आवश्यकता है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि विश्व के दूसरे देशों में तेल शोधक कारखानों में आने वाली उत्पादन लागत की तुलना में हमारे देश के तेल शोधक कारखानों की उत्पादन लागत अधिक है ;

(ग) यदि नहीं, तो देश में और विदेशों में कार्यरत तेल शोधक कारखानों की औसत उत्पादन लागत अंतर्राष्ट्रीय आधार पर कितनी है ;

(घ) क्या स्वदेशी तेल शोधक कारखानों की उत्पादन लागत कम करने के लिए सरकार द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ; और